नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन से गरीब कल्याण

स्वदेश सिंह

नोटबंदी अभियान और बाद में देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के कदम से कालाधन रखने वालों, नकली नोटों का कारोबार करने वालों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगर उनका नुकसान हो रहा है तो लाभ किसका होगा। ये लाभ अब समाज के अंतिम तबके तक सीधे और बड़ी मात्रा में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कालाबाजारियों और भ्रष्ट लोगों को दुश्मन करार देते हुए कहा कि अगर दुश्मन भागेगा तो हम उसे दौड़ कर पकड़ेंगे। अगर वो अपनी रणनीति बदलेगा तो हम अपनी रणनीति भी बदलेंगे

आजादी के बाद शायद ही ऐसी कोई नीति, कार्यक्रम या अभियान हो जिसने हर एक आम भारतीय के जीवन पर इतना सीधा असर डाला हो। जितना विमुद्रीकरण ने डाला है। विमुद्रीकरण या नोटबंदी का अभियान, केंद्र सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका हर भारतीय के जनजीवन पर खासा असर पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने इसे असफल भी बताया है। वहीं बहुत से लोगों ने इसे गेम चेंजर भी कहा है और इसके कई लाभ भी गिनाएं हैं। शुरुआती रुझानों और प्रधानमंत्री के 31 दिसंबर, 2016 के भाषण से पता चलता है कि इस अभियान के दूरगामी परिणाम होंगे।

नोट जमा करने की अवधि खत्म होने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री की घोषणाओं ने साफ कर दिया कि नोटबंदी का सीधा लाभ इस देश के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग तक पहुंचेगा। उन्होंने निम्न घोषणाएं कीं-

- छोटे व्यापारियों के लिए लघु उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट की सीमा 20 से बढ़ाकर 25 फीसदी।
- जो व्यवसायी डिजिटल लेन-देन करेंगे उनके लिए वर्किंग कैपिटल लोन 20 से बढ़ाकर 30 फीसदी।
- मुद्रा योजना के तहत होने वाला कुल धन आवंटन दोगुना होगा जिसके तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता।
- जिन किसानों ने रबी की फसल के लिए लोन ले रखा था उन्हें ऋण से 60 दिन की छूट।
- नाबार्ड कोष में सरकार 20000 करोड़ रुपए देगी, जिससे किसानों को सस्ती दर पर उधार मिल सके।
- 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे डेबिट कार्ड में बदला जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों की संख्या में 33 फीसदी वृद्धि।
- शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाख तक के लोन पर 4 फीसदी और 12 लाख तक के लोन पर 3 फीसदी की छूट।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख तक लोन लेकर घर बनाने पर 3 फीसदी की छूट।
- वरिष्ठ नागरिक द्वारा 7.5 लाख रुपए तक जमा करने पर अगले दस साल तक 8 फीसदी की दर से ब्याज।
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपए तक की मदद।

नोटबंदी का उद्देश्य

नोटबंदी को समग्रता में समझे जाने की जरूरत है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार मिटाने के साथ-साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े गरीब आदमी का कल्याण था। सरकार ने इस दिशा में बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था। केंद्र में सरकार आने के तुरंत बाद कैबिनेट ने पहला निर्णय जहां कालेधन के खिलाफ एसआईटी के गठन का लिया, वहीं स्वैच्छिक आयकर योजना, जनधन योजना, ब्लैकमनी एक्ट, डीआरटी संशोधित लॉ, बेनामी सम्पत्ति एक्ट जैसे कानूनों को पास करके कालेधन के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यवस्थागत एवं कानूनी प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए कदम उठाये गए। देश में जीएसटी कानून के भविष्य में कुशल उपयोग के लिए और कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक हैं। जेएनयू और आईआईएमसी, नई दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद कई मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं। सामाजिक-राजनैतिक विषयों पर शोधपरक लेखन। ईमेल : swadesh171@gmail.com

लिए विमुद्रीकरण आवश्यक था। आज देश में बैंकों के पास ऋण देने के लिए पहले से ज्यादा पैसा है और ब्याज दरें नीचे गिर रही हैं। अब अनौपचारिक और औपचारिक, दोनों अर्थव्यवस्थाएं ठीक तरीके से आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे राज्यों और केंद्र को अधिक आय होगी और हम एक साफ और बढ़ी हुई जीडीपी की तरफ बढ़ेंगे।

विमुद्रीकरण से पहले कालाधन जमा कराने की जो मुहिम शुरू की गई, उसके तहत करीब 62 हजार करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया। 8 नवबंर, 2016 को नोटबंदी लागू हुई, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। सरकार ने पूरे अभियान के दौरान दो बातों पर जोर दिया- नकली नोट और कालेधन को बाहर निकाल कर भ्रष्टाचार कम करना और नगदरहित लेन-देन की तरफ आगे बढ़ना। हम कह सकते हैं कि जिस मात्रा में देश में कालाधन था और कर के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या जितनी कम थी उसे ठीक करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाने जरूरी थे। नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। नोटबंदी कालेधन और नकली नोटों का कारोबार करने वालों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक हमला है। इससे उन लोगों का मनोबल टूटा है, जो कालेधन और नकली नोटों से एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाकर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था के साथ ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे।

नोटबंदी का असर

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से 86 प्रतिशत करेंसी नोट बंद हो गए। इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के सामने की लंबी कतारों में खड़े आम लोगों, छोटे व्यापारियों और पर्यटकों को परेशानी तो झेलनी पड़ी। सरकार के इस निर्णय से हमारी नगदी अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा। नवंबर और दिसंबर के महीने में लोगों को नगदी की समस्या भी झेलनी पड़ी।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जल्द से जल्द नगदी की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन कई स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण इसमें थोड़ा समय लगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्तीय स्थिरता की अर्धवार्षिक रिपोर्ट की भूमिका में लिखा कि हम सबको विमुद्रीकरण के कारण थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं लेकिन लंबे समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये अभियान घरेलू अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देगा।

एक साक्षात्कार के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के असर के बारे में बताते हुए कहा कि इस अवधि में प्रत्यक्ष कर में 14.4 फीसदी, अप्रत्यक्ष कर में 26.2 फीसदी, केंद्रीय आबकारी कर में 43.3 फीसदी और सीमा कर में 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बीमा, पर्यटन, पेट्रोलियम और म्यूचुअल फंड के कारोबार में भी गुणात्मक बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले साल की तुलना में रबि की फसल की बुआई में भी 6.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

ऐसा माना गया कि नोटबंदी के कदम से कश्मीर में आतंकवादियों, छत्तीसगढ़ में माओवादियों और पाकिस्तान से नकली नोटों का कारोबार करने वालों को गहरा धक्का लगेगा क्योंकि ये सारी गतिविधियां कालेधन या नकली नोटों के माध्यम से ही अंजाम दी जाती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में नकली नोट छापने वाले दो प्रेस बंद हुए, कश्मीर में हो रही हिंसा में 60 फीसदी की कमी आई और हवाला के कामकाज में भी 50 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है।

संसाधन जितना नीचे तक, जितनी अधिक मात्रा में पहुंचेंगे सामाजिक न्याय उतना ही सुनिश्चित होगा। नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री ने वितरणीय न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का ये कारगर कदम उठाया है।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विमुद्रीकरण के इस कदम का एक मुख्य लक्ष्य भारत की समानांतर अर्थव्यवस्था पर घातक चोट पहुंचाना था, जो सरकारी खजाने और घरेलू अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। संजय मूकीम जोकि बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच में अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि ये समानांतर अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद का करीब 25-30 फीसदी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कालेधन की अर्थव्यवस्था की तरफ जाने वाले धन में कमी आएगी और वो औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी।

छोटी अवधि का एक लाभ ये भी हुआ है कि एक तरफ लोग बैंकों में पुरानी करेंसी जमा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नकद निकासी की सीमा निर्धारित कर दी गई है जिससे बैंकों के पास भारी मात्रा में नगद जमा हो गया है। इसकी वजह से बैंकों ने तमाम तरह की रियायतें देनी शुरू कर दी हैं और अब सस्ती दर पर लोन मिल रहे हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य ने एक साक्षात्कार में कहा कि लोन की दर जल्द ही और कम होगी। एक अन्य बड़े बैंक के अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि सरकार द्वारा डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन दिए जाने से बैंकों में नगदी हमेशा बनी रहेगी। इस कदम से कालाधन अब बैंकों में आ जाएगा, जिससे ना सिर्फ सरकार की देनदारी घटेगी, बल्कि सरकार का कोष भी बढ़ेगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए नोटबंदी के कदम की सराहना की है और कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को अब नगदरहित लेन-देन की दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए। नगदरहित व्यवस्था के दम पर भारत एक बड़े बदलाव का साक्षी बन सकता है। एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन टिरोल ने भी सरकार के कदम को सही बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने नोटबंदी करके भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की है।

डिजिटल लेन-देन

आज देश में 107 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है, 147 करोड़ बैंक अकाउंट में से 117 करोड़ सेविंग अकाउंट एवं 25 करोड़ जनधन अकाउंट है। 35 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन, 40 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर से खातों का जुड़ाव एवं 75 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड भारत की डिजिटल कारोबारी व्यवस्था के विकास हेतु एक सक्षम प्लेटफार्म है। केंद्र सरकार द्वारा नगदरहित लेन-देन बढ़ाने के लिए भीम ऐप, यूपीआई, यूएसएसडी, एईपीएस एवं रुपे-कार्ड के प्रयोग को बढ़ाना एक अच्छा कदम है।

इसलिए नोटबंदी के बाद सरकार ने नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने का जिम्मा उठाया जिसके तहत लोगों को डिजिटल लेन-देन करने पर तरह-तरह की रियायतें दी जा रही हैं। लोगों को जब नगदरहित लेन-देन

की आदत पड़ने लगेगी तो पैसा बैंकों में ही रहेगा इससे बैंक लोगों को अतिरिक्त लाभ पहुंचा सकेंगे। नगदरहित लेन-देन से लंबे समय में कई फायदे होंगे जो समय के साथ ही दिखेंगे। इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, कालेधन पर लगाम लगेगी, नए आयकरदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

न्याय और गरीब कल्याण

राजनीति की एक परिभाषा होती है- मूल्यों का आधिकारिक वितरण। ये वितरण नीचे तक तभी पहुंचेगा। जब आपके पास वितरण करने के लिए समुचित मात्रा में संसाधन और मूल्य होंगे क्योंकि हमारे यहां कई स्तर पर संसाधनों का रिसाव (लीकेज) हो जाता है। ये संसाधन जितना नीचे तक, जितनी अधिक मात्रा में पहुंचेंगे सामाजिक न्याय उतना ही सुनिश्चित होगा। नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री ने वितरणीय न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का ये कारगर कदम उठाया है।

पहले बैंक निजी क्षेत्र में हुआ करते थे लेकिन 1969 में उनका राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया जिसका उद्देश्य बैंकों को गरीबों और समाज के पिछड़े तबकों तक पहुंचाना था। जिससे उन्हें वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके। ऐसा सोचा गया था कि पूंजीपति का पैसा जब बैंक में पहुंचेगा तो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा और गरीबों को लाभ होगा। लेकिन इतने सालों में हम समाज के सभी वर्गों तक बैंक की सुविधा ही नहीं पहुंचा पाए थे। केंद्र सरकार ने इसीलिए सबसे पहले 25 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट जनधन योजना के तहत खोले और करोड़ों की संख्या में रूपे कार्ड बांटे। अब इन रूपे कार्ड को डेबिट कार्ड में बदला जा रहा है।

आज भारी मात्रा में लोगों का पैसा बैंकों में पहुंच चुका है। अगर सही ढंग से नगदरहित व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ते गए तो बाजार में कालेधन में कमी आती जाएगी। इससे कर देने वालों की संख्या बढ़ेगी और सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी और गरीब कल्याण योजनाओं में धन का आवंटन बढ़ेगा। ऐसे वातावरण में सरकार समाज के कमजोर तबके के लिए अधिक से अधिक नीतियां और कार्यक्रम और बड़े बजट के साथ ला सकेगी। औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने से असंगठित क्षेत्र में हो रही लेन-देन को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। इन सबकी एक बानगी प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा में मिलती है। हम आशा कर सकते हैं कि आम बजट -2017 में भी ऐसी ही कई घोषणाएं सुनने को मिलेंगी।

नोटबंदी ने एक झटके में समाज में बराबरी लाने का भी काम किया है जो किसी और तरीके से करना नामुमकिन था। जिस आदमी के पास कालाधन था उसने कालेधन सरकारी खजाने में जमा करवाया और भारी टैक्स चुकाया। कइयों का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया क्योंकि सरकार ने पैसा जमा करने की एक सीमा तय कर दी थी। रियलस्टेट बाजार का एक बड़ा हिस्सा कालेधन से खड़ा हुआ था जिससे मकान और जमीन के दाम बहुत ऊंचे थे। सरकार के इस कदम से मकान और जमीन के दाम 30-50 फीसदी तक नीचे आ गए।

हवाला के माध्यम से बाजार में घूमते कालेधन की वजह से जमीन, मकान, सोना-चांदी की कीमत में बेतहाशा वृद्धि होती थी। नोटबंदी से अब इन सबके दामों में भारी कमी आ गई है। लोगों को उतनी ही मात्रा में कालाधन जमा करने में अब लंबा समय लगेगा। इस तरह से कालाधन का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों में करने वालों की संख्या में भी कमी आएगी और देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियां भी कम होंगी।

नोटबंदी की वजह से लोग अब अपना पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में कर मिला करेगा और सरकार ये पैसा समाज की बेहतरी में लगाएगी और अस्पताल, शिक्षण संस्थान, सड़क और जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए दूसरी अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी।

अगर किसी की हानि होती है तो किसी का लाभ भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी अभियान और बाद में देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के कदम से कालाधन रखने वालों, नकली नोटों का कारोबार करने वालों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगर उनका नुकसान हो रहा है तो लाभ किसका होगा। ये लाभ अब समाज के अंतिम तबके तक सीधे और बड़ी मात्रा में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कालाबाजारियों को और भ्रष्ट लोगों को दुश्मन करार देते हुए कहा कि अगर दुश्मन भागेगा तो हम उसे दौड़ कर पकड़ेंगे। अगर वो अपनी रणनीति बदलेगा तो हम अपनी रणनीति भी बदलेंगे। अगर भ्रष्ट लोग बेइमानी की दूसरी तरकीब लाएंगे तो हम भी नए तरीके अपनाएंगे लेकिन अब उन्हें पनपने नहीं देंगे।

सत्ताधारी दल भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव में माना गया है कि देशहित का यह (नोटबंदी) कार्य भारत के गरीबों के आर्थिक समायोजन, पारदर्शी शासन एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बड़ा पड़ाव है। विमुद्रीकरण की यह प्रक्रिया कर नहीं देने वालों के कालेधन को गरीबों और कमजोरों में वितरण से जुड़ी है। ❑

संदर्भ

- http://www.dnaindia.com/india/report & demonetization & pm & modi & criticises & opposition & for & openly & protecting & the & dishonest & slams & manmohan & singh & 228757
- http://www.dnaindia.com/money/report & rbi & governor & urjit & patel & upbeat & about & demonetization & effects & despite & short & term & disruptions & 228755
- http://www.indialivetoday.com/fm & arun & jaitley & talks & benefits & demonetization & economy & thanks & indian & peopl//87493.html
- http://economictimes.indiatimes.com/news/politics & and & nation/note & ban & takes & toll & on & terror & pak & counterfeit & presses & close & kashmir & violence & dips & 60/articleshow/ 56383135.cms\ from¾mdr
- http://www.cnbc.com/2016/11/21/india & demonetization & news & eÛpect & short & term & pain & analysts & say & as & growth & eÛpected & to & take & a & hit.html
- http://www.thehindu.com/ news/ national/ Cashless & economy & is & a & boon & says & Nobel & laureate & Muhammad & Yunus/article 16994985.ec
- http://www.indiane conomy.net/ splclassroom/ 314/what & are & the & longterm & benefits & of & demonetization/ #sthash.HSqXkVeV.dpuf
- http://indiaarising.com/15 & mind & blowing & immediate & benefits & demonetization & media & will & never & tellè
- http://www.forbes.com/sites /wadeshepard/ 2016/12/12/ one & month & in & whats & the & impact & of & indias & demonetization & fiasco/ #3f670c 1862eb
- http://www.japantimes.co.jp/ opinion/ 2016/ 11/27/ commentary/ world & commentary/ economic & political & risks & indias & demonetization/ #AWGX & sLaGPR1
- http://www.bjp.org/en/media & resources/ press & releases/ economic & resolution & passed & in & bjp & national & cÛecutive & meeting & at & ndmc & convention & centre & new & delhi & 07 & 01 & 2017
- http://pib.nic.in/newsite/ Print Release AaspÛ\ relid¾156204 & utm_source¾ dlvrAit & utm_medium¾twitter

पृष्ठ 46 से जारी...

इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, एसेसरीज के अलावा ऑनलाइन माध्यम से राशन *ग्रॉसरी* की सामग्री और फल-सब्जियों के खरीददारों की तादात में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बिगबास्केट, आटादाल डॉट कॉम, लोकल बनिया डॉट कॉम सहित तमाम छोटे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीददारी करने वालों की बढ़ती संख्या ने ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को और ज्यादा लोकप्रियता प्रदान की है।

इतना होने के बावजूद बाजार के विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में ऑनलाइन भुगतान को लेकर ज्यादा आशान्वित हैं। दरअसल, नगदरहित लेन-देन करने वाला एक बड़ा वर्ग महानगरों से आता है और टू एवं थ्री टीयर शहरों एवं गांवों में अब भी इस क्षेत्र से उम्मीद के मुताबिक लोग नहीं जुड़ सके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा 20 हजार करोड़ रूपए के निवेश से देश में ब्रॉडबैंड हाइवे के निर्माण करने और देश भर के 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ने की घोषणा की गयी है। एक बार ब्रॉडबैंड हाइवे स्थापित हो गया तो ग्रामीण इलाकों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने और नगदरहित अर्थव्यवस्था से जोड़ने में तेजी आने की उम्मीद है।

भारत में भुगतान उद्योग मुख्यत: दो भाग में बंटा हुआ है। मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट। मोबाइल बैंकिंग में जहां आईसीआईसीआई, एचडीएफसी व एसबीआई जैसे बड़े बैंकों का दबदबा है वहीं मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं जैसे एयरटेल, आईडिया, वोडाफोन इत्यादि के साथ साझेदारी कर सेवा प्रदान कर रहीं हैं।

वर्ष 2019 तक भारतीय भुगतान गेटवे क्षेत्र का कुल लेन-देन 8,172.7 बिलियन डॉलर तक पहुचने की उम्मीद है। विदित हो कि ये सभी अनुमान देश में नोटबंदी लागू होने से पूर्व के हैं। केन *रिसर्च* के मुताबिक सुविधाओं से वंचित ग्रामीण आबादी और सख्त सरकारी नियम इस क्षेत्र के विकास में रोड़ा हैं लेकिन जिस प्रकार वर्तमान सरकार उदारवादी नीतियां अपना रही है उससे यह उद्योग संभावनाओं से भरा प्रतीत हो रहा है।

मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में मोबाइल की सहायता से लेन-देन करने वालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। ऑनलाइन भुगतान के प्रति जागरुकता और कार्ड आधारित डिजिटल लेन-देन ने विभिन्न भुगतान गेटवेज को लोकप्रियता प्रदान की है। वित्तवर्ष 2012-2014 के बीच भुगतान इंडस्ट्री ने 142.9 प्रतिशत की उछाल दर्ज की।

केन *रिसर्च* द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार वर्ष 2019 तक भारतीय भुगतान गेटवे क्षेत्र का कुल लेन-देन 8,172.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदित हो कि ये सभी अनुमान देश में नोटबंदी लागू होने से पूर्व के हैं। केन *रिसर्च* के मुताबिक सुविधाओं से वंचित ग्रामीण आबादी और सख्त सरकारी नियम इस क्षेत्र के विकास में रोड़ा हैं लेकिन जिस प्रकार वर्तमान सरकार उदारवादी नीतियां अपना रही है उससे यह उद्योग संभावनाओं से भरा प्रतीत हो रहा है।❑

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

योजना
आगामी अंक
मार्च 2017
केन्द्रीय बजट 2017-18
(विशेषांक)